

50 Years of Arunachal Pradesh

Arunachal Pradesh enjoyed a special identity as the North East Frontier Tract (NEFT) during the late 19th century British era. In 1954, the region was designated as NEFA through introduction of the North East Frontier (Administration) Regulation, 1954. NEFA was first brought under the Ministry of External Affairs, and in August 1965, the administration was transferred to the Ministry of Home Affairs, which supervised and controlled the region till 1972 when it gained the status of a Union Territory.

Modern-day Arunachal Pradesh, owes much to the vision of its founding fathers—the members of the erstwhile Agency Council, a body that functioned like the legislative assemblies of other states and was formed in December 1969. It was in the very first sitting of the Agency Council on December 3, 1969, that it was decided that NEFA's capital should be within its boundaries. The decision to change NEFA's name to Arunachal Pradesh was taken in the Agency Council's second session which took place on August 10–11, 1970 in Shillong. Three names were considered—Udayachal (meaning, land of the sunrise), Brahma Mandal (the land of the Brahma) and Arunachal (the land of the rising sun). After intense discussions, the Council members unanimously selected Arunachal Pradesh as the name of the territory—a decision that was accepted by the Government of India.

On January 20, 1972 NEFA was rechristened as Arunachal Pradesh and was declared a Union Territory, a beginning into its self-governance. It would take another 15 years for this Union Territory to gain Statehood, which it did on February 20, 1987. Today, it is a fast developing state of 26 districts, each resplendent with its unique culture and tradition.

The Green State of Arunachal Pradesh has multitude of potentials which is being tapped for becoming *Atma Nirbhar*. In the last five decades, the state has attained a distinct mark on the map, notably in the realm of tourism. Arunachal is fast developing as a go-to adventure tourism destination with various opportunities in white river rafting, paragliding, trekking, biking destinations and wild life & bird watching activities etc.

The Government of Arunachal Pradesh has approved and adopted the first of its kind, 'Pakke Tiger Reserve 2047 Declaration on Climate Change Resilient and Responsive Arunachal Pradesh' or "Pakke Declaration" in November 2021 in alignment with COP 26 action plan. It focuses on a multi-sectoral approach to low-emission and climate-resilient development based on five broad themes or Panch Dharas aligning our annual action plan budget with SDGs.

The Hydropower sector has seen a boom with development of mini & micro hydels and dams all across the state. In terms of Agriculture & Horticulture sector, Arunachal Pradesh is the highest producer of Kiwi in the Country. The state is also attempting to introduce new potential fruits in the State like blue berry and walnuts which are not endemic to the state. The state is also a rich reserve for bamboos.

January 20, 2022 marked the 50 years of the state's identity as Arunachal Pradesh. The state is celebrating a month long festival to commemorate it. As a testimony to the historic moment of naming of Arunachal Pradesh in Ziro on 20 January, 1972, the Celebration commenced with an inaugural ceremony at Ziro on 20 January, 2022. The Celebration will culminate at the capital, Itanagar on 20 February, 2022 marking the Valedictory celebration of 50 years of Arunachal and the initiation of 36th Statehood Day celebration.

The logo of the celebration has been created after conducting a competition along the theme of 'Celebrating Past... Nurturing Future'. The logo consists of the state bird, Hornbill, the state flower, Foxtail Orchid and the current political map of Arunachal Pradesh.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on 50 Years of Arunachal Pradesh.

Credits:

Stamp/ Brochure	: Shri Suresh Kumar
FDC/Cancellation Cachet	: Smt. Nenu Gupta
Text	: Referenced from contents provided by the proponent

डाक विभाग
Department of Posts

विवरणिका BROCHURE

अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष
50 Years of Arunachal Pradesh



celebrating past.... nurturing future

अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर मार्ग (एनईएफटी) के रूप में अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष पहचान हुआ करती थी। 1954 में उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर (प्रशासन) विनियम, 1954 लागू करके इस क्षेत्र को एनईएफ नाम दिया गया। एनईएफ का प्रशासन पहले विदेश मंत्रालय करता था, जिसे अगस्त, 1965 में गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। गृह मंत्रालय ने 1972 तक इस क्षेत्र की निगरानी एवं नियंत्रण किया, जब तक इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्राप्त नहीं हो गया।

आज का अरुणाचल प्रदेश अपने संस्थापकों के विजन का आभारी है, जो तत्कालीन एजेंसी परिषद के सदस्य थे। यह परिषद एक निकाय था, जो अन्य राज्यों के विधान सभा का कार्य करता था। इसका गठन 3 दिसंबर 1969 को हुआ था। इस एजेंसी परिषद की 3 दिसंबर, 1969 को आयोजित पहली ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनईएफ की राजधानी इसकी सीमाओं के अंदर ही होनी चाहिए। एजेंसी परिषद की दूसरी बैठक 10-11 अगस्त 1970 को शिलांग में हुई, जिसमें एनईएफ का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया गया। तीन नामों पर विचार किया गया था उदयाचल (सूर्योदय की भूमि), ब्रह्मा मंडल (ब्रह्मा की भूमि) तथा अरुणाचल (उगते हुए सूर्य की भूमि)। गहन चर्चा के बाद, परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस संघ राज्य क्षेत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश चुना, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी।

20 जनवरी, 1972 को एनईएफ का नामकरण 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया, इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया और इस प्रकार स्व-शासन की शुरुआत हुई। संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में 15 वर्ष लगते हैं, जो 20 जनवरी, 1987 को पूरे हो गए। अब अरुणाचल प्रदेश 26 जिलों वाला सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाला राज्य है और इसका प्रत्येक जिला अपनी विलक्षण संस्कृति एवं परम्परा से दीप्तिमान है।

हरे-भरे अरुणाचल प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और 'आत्म निर्भर' बनने के लिए उनका उपयोग भी किया जा रहा है। विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में विगत पांच दशकों में इस राज्य ने मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है क्योंकि यहां व्हाइट रिवर रॉपिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, बाइकिंग, वन्य जीव एवं पक्षी विहार दर्शन आदि सहित साहसिक पर्यटन के अनेक अवसर हैं।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सीओपी 26 कार्य योजना के अनुसार नवंबर 2021 में अपनी तरह के पहले 'पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाउडमेट चेज रिसाइलिंग एंड रिस्पांसिव अरुणाचल प्रदेश' या "पक्के डिक्लेरेशन" योजना को अनुमोदित करके अपनाया था। यह कार्य योजना एसडीजी के अनुसार हमारे वार्षिक कार्य योजना बजट को ढाल कर पांच बड़े विषयों या पांच धाराओं पर आधारित न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु की हानि किए बिना विकास करने के लिए बहुक्षेत्रीय उपाय किए जाने पर केन्द्रित है।

राज्य भर में लघु एवं सूक्ष्म विद्युत संयंत्र तथा बांध बनाए जाने के कारण जल विद्युत के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में नीलबंदरी (ब्लूबेरी) तथा अखरोट जैसे नए फलों के उत्पादन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो अभी यहां नहीं पाए जाते। राज्य में बांस का भी समृद्ध भंडार है।

20 जनवरी, 2022 को अरुणाचल प्रदेश नाम दिए जाने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्य इसे यादगार बनाने के लिए पूरे एक महीने तक चलने वाला उत्सव मना रहा है। चूंकि 20 जनवरी, 1972 को जाइरो शहर में ही 'अरुणाचल प्रदेश' नाम रखा गया था, अतः इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए इस समारोह का उद्घाटन समारोह 20 जनवरी, 2022 को जाइरो में ही किया गया। समारोह का समापन 20 फरवरी, 2022 को राजधानी ईटानगर में किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने का समापन समारोह तथा 36 वां पूर्ण राज्य दिवस समारोह का प्रारंभ भी होगा।

समारोह का लोगो 'सेलिब्रेटिंग पास्ट... नर्चरिंग फ्यूचर' की थीम पर प्रतियोगिता आयोजित करके बनाया गया था। इस लोगो में राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय पुष्प फाक्सटेल ऑर्किड तथा अरुणाचल प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र शामिल है।

डाक विभाग अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष पर स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:

डाक टिकट/ विवरणिका : श्री सुरेश कुमार
प्रथम दिवस आवरण/ : श्रीमती नीनू गुप्ता
विरूपण कैश :
पाठ : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से संदर्भित

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें	: 404225
Stamps Printed	: 404225
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00